बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 152

कर्जमुक्त होती आरआईएल

रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) पिछले कुछ समय के दौरान अपने बढ़ते कर्ज के कारण चर्चा में रही। कंपनी ने मोबाइल टेलीफोन में अरबों डॉलर का जो भारी भरकम निवेश किया है उसका प्रतिफल अभी उसे मिलना शेष है। इस कारोबार से अब तक इतना निवेश नहीं आ सका है जो इस उद्यम में लगने वाले भारी भरकम निवेश को उचित ठहरा सके। इसके कारण कंपनी के ऋण अनुपात में काफी इजाफा हुआ है जबकि बीते कुछ वर्षों के दौरान कंपनी का मुक्त नकदी प्रवाह नकारात्मक रहा है। वित्त वर्ष 2015 में जहां कंपनी की देनदारी 19 अरब डॉलर थी, वहीं 2019 में यह बढ़कर 65 अरब डॉलर हो चुकी है। इस परिदृश्य में विदेशी ब्रोकरेज कंपनी क्रेडिट सुइस ने आरआईएल की रेटिंग कम कर दी थी और एक सप्ताह पहले इसके लक्षित मूल्य में एक तिहाई की कटौती कर दी।चिंताएं वाजिब थीं। आरआईएल ने वित्त वर्ष 2019 में शुद्ध ऋण और इक्विटी अनुपात 0.58 गुना दर्शाया था जो हाल के वर्षों के उच्चतम स्तर में से एक था। इस बीच गत वित्त वर्ष में ब्याज कवरेज अनुपात गिरकर 5.6 गुना रह गया। यह बीते 15 वर्षों में सबसे कम है। अपनी रिपोर्ट में क्रेडिट सुइस ने कहा कि आरआईएल का मुक्त नकदी प्रवाह वित्त वर्ष 2015 से नकारात्मक रहा है और वित्त वर्ष 2021 तक इसके ऐसा ही रहने की आशंका है क्योंकि उसके मूल कारोबार ईंधन रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल में मार्जिन का दबाव है। कंपनी की कुल देनदारी बढ़कर 65 अरब डॉलर हो चुकी है क्योंकि कच्चे तेल, जियो फोन फाइनैंसिंग और ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन में कंपनी का काफी बकाया है। समान अवधि में कंपनी का कुल ब्याज भुगतान 1.2 अरब डॉलर से बढ़कर 4 अरब डॉलर हो गया। यह 2019 में कंपनी की ब्याज और कर पश्चात आय के करीब 44 फीसदी के बराबर है।

ऐसे में सोमवार को सऊदी अरामको को रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कारोबार में 20 फीसदी का इक्विटी साझेदार बनाने का निर्णय कंपनी के निवेशकों के लिए सुखद है। निवेशक इस बात को लेकर चिंतित थे कि कंपनी अपने जियो उपक्रम में चरणबद्ध उधारी के माध्यम से निवेश कर रही थी। कंपनी के रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कारोबार का सौदा मूल्य करीब 75 अरब डॉलर है। यानी आरआईएल को एकबारगी करीब 15 अरब डॉलर की राशि मिलेगी। कंपनी अपने ईंधन रिटेल कारोबार की 49 फीसदी हिस्सेदारी ब्रिटिश पेट्रोलियम को बेचकर करीब एक अरब डॉलर की राशि जुटाने जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी से दीर्घावधि की कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा आरआईएल निवेश का इस्तेमाल कर्ज कम करने या विस्तार में कर सकती है। कंपनी ने हाल ही में अपनी टावर और फाइबर परिसंपत्तियों में से 16.5 अरब डॉलर मूल्य की परिसंपत्ति को दो अलग-अलग निवेश न्यासों में बांट दिया। कंपनी का इरादा वहां बाहरी निवेशक जुटाने का है। अनुषंगियों की बात करें तो कंपनी की योजना जियो और रिलायंस रिटेल का मुद्रीकरण करने तथा अचल संपत्ति और वित्तीय निवेश का मूल्य हासिल कर मार्च 2021 तक कर्ज मुक्त हो जाने की है। रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कंपनी की कुल कर और ब्याज पूर्व आय का 79 फीसदी है। गत वित्त वर्ष में जियो की कर और ब्याज पूर्व हिस्सेदारी 13.3 फीसदी थी।

बहरहाल आरआईएल की कुल परिसंपत्तियों में दोनों कारोबारों की समान हिस्सेदारी है। कंपनी को आगे जियो के पूंजी पर प्रतिफल में सुधार करना होगा जो अभी 3 फीसदी है। यह तभी होगा जब कंपनी मोबाइल शुल्क दर बढ़ाएगी या अपने उपभोक्ता आधार से पैसे जुटाएगी। सोमवार को कंपनी की वार्षिक आम बैठक में आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि उन्हें इस बात में संदेह नहीं कि कंपनी दुनिया की सबसे मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियों में शामिल होगी। अंशधारक भी चाहेंगे कि वे अपनी बात पर खरे उतरें।

अजय मोहंती

संरचनात्मक बदलावों की सरकार से उम्मीद बेमानी

आर्थिक सुस्ती करीब आने के साथ ही सरकार के कदमों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। देवाशिष बसु का कहना है कि संरचनात्मक सुधारों के बगैर कोई भी कदम असरदार नहीं हो पाएगा

पिछला माह काफी घटना-प्रधान रहा। कैफे कॉफी डे के संस्थापक वी जी सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली और अपने पीछे एक चिट्ठी छोड़ गए जिसमें बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों को स्वीकार करने के साथ ही वह कर अधिकारियों के हाथों उत्पीड़न के संकेत भी दे गए। इस सुसाइड नोट के सामने आने के बाद आई प्रतिक्रियाएं राजनीति, उद्यमशीलता, जोखिम उठाने से जुड़ी मुश्किलों और अत्यधिक कर्ज से जुड़े तमाम पहलुओं को रेखांकित करती हैं। अधिकांश प्रतिक्रियाओं में भावनाओं की अधिकता थी, लिहाजा वे असली मुद्दे से भटक भी गईं। अधिक तर्कसंगत समझ के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि खुदकुशी का ताल्लुक किसी व्यक्ति की भौतिक स्थिति से नहीं बल्कि उसकी मानसिक स्थिति से होता है। आखिर, कई लोग अपने करीबियों समेत सब-कुछ गंवा देने के बावजूद खुदकुशी का रास्ता नहीं अपनाते हैं।

सिद्धार्थ की मौत मौजूदा आर्थिक सुस्ती की फिर से परीक्षा करने का एक मौका देती है। भारत में करीब 50 फीसदी घरेलू यात्री वाहनों की निर्माता मारुति सुजूकी को जुलाई 2019 में बिक्री में 33.5 फीसदी गिरावट का सामना करना पड़ा है और उसने अपने अस्थायी कर्मचारियों में छह फीसदी की कटौती कर दी है। जनवरी-मार्च तिमाही में भारत से आने-जाने वाले हवाई यात्रियों की संख्या 3.8 फीसदी की दर से ही बढ़ी है जो गत चार वर्षों की सबसे धीमी रफ्तार है। इस तरह के निराशाजनक आंकड़ों की मीडिया में भरमार है।

आर्थिक सुस्ती इतनी गंभीर है कि मौजूदा सरकार के इरादों और क्रियाकलाप को लेकर आशंकित कारोबारियों ने अब खुलकर अपनी हताशा जतानी शुरू कर दी है। हाल-फिलहाल तक इस सरकार के हरेक कदम की तारीफ करते रहे टी वी मोहनदास पई ने अब उस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पई कहते हैं, 'कर आतंक काफी बढ़ गया है। अनुपालन का बोझ भी बहुत अधिक हो चुका है। हर तरफ डर का माहौल है। सरकारी अधिकारियों के बीच ऐसी भावना है कि सभी कारोबारी धूर्त हैं और हमें उन पर नकेल कसनी चाहिए। मैंने कभी भी मुंबई में इस तरह का माहौल एवं मनोदशा नहीं देखी है। कारोबारियों ने उम्मीद करना ही छोड़ दिया है।'

बजाज ऑटो के चेयरमैन राहुल बजाज भी ऐसी ही चिंताएं जता चुके हैं। बजाज के शब्दों में, 'न तो मांग है और न ही निजी निवेश हो रहा है। ऐसे में वृद्धि कहां से होगी? आसमान से तो टपकेगी नहीं।' लार्सन ऐंड टुब्रो के प्रमुख ए एम नायक ने भी कहा है कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल 6.5 फीसदी की दर से भी बढ़ती है तो हमें खुशकिस्मत समझना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों पर यकीन न रह जाने ('आंकड़ों की विश्वसनीयता पर चुनौतीपूर्ण स्थिति') की बात करते हुए कहा है कि वास्तविक वृद्धि का अंदाजा लगाने के लिए आपको अपने निजी निर्णय का इस्तेमाल करना होगा। जनवरी-मार्च तिमाही में आर्थिक वृद्धि घटकर पांच वर्षों के न्यूनतम स्तर 5.8 फीसदी पर दर्ज की गई।

महज कुछ महीने पहले पई उन 131 चार्टर्ड अकाउंटेंट में शामिल थे जिन्होंने भारत के आर्थिक आंकड़ों पर सवाल उठाने वाले और शीर्ष सांख्यिकी निकाय में राजनीतिक दखल का आरोप लगाने वाले 100 विद्वानों की चिंताओं को नकारा था। निराशा के स्वर इतने तेज होते जा रहे हैं कि कुछ अंग्रेजी चैनलों ने अचानक ही पलटी खा ली है। इस सरकार के एजेंडा का खुलकर प्रचार में लगे रहने वाले समाचार चैनल आम तौर पर लुप्तप्राय विपक्ष को ही लताड़ने में लगे रहते हैं लेकिन अब वे प्रभावित कारोबारियों को भी जगह देने लगे हैं।

कांग्रेस की अगुआई वाली संप्रग सरकार के 10 वर्षों के शासनकाल में दो बातों-नीतिगत पंगुता और दोस्ताना पूंजीवाद का काफी शोर था। लेकिन आज कोई भी इनका जिक्र नहीं करता है। आप इस सरकार की कई बातों के लिए आलोचना कर सकते हैं लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को दशकों से आक्रांत कर रखी इन बुराइयों की इस सरकार में कोई जगह नहीं है। किसी तरह की नीतिगत पंगुता से दूर यह सरकार काफी अधिक सक्रिय है और सैकड़ों कानूनों में बदलाव एवं नई योजनाएं लेकर आई है। फिर भला हमें इतने खराब नतीजे क्यों देखने को मिल रहे हैं?

इसका जवाब बड़ा सरल है। दरअसल इस सरकार की नीतियां एवं क्रियाकलाप बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं हैं। वृद्धि एवं न्याय का पहला सिद्धांत राज्य का हस्तक्षेप एवं प्रभुत्व को कम करना है। सरकार से कारोबारियों एवं नागरिकों के लिए समानुभूति रखने की उम्मीद करना काफी अधिक है, भले ही नौकरियों एवं करों में होने वाली सारी वृद्धि इन्हीं लोगों से आती है। यह सरकार कम-से-कम इतना तो कर ही सकती है कि वह हरेक कारोबारी को धूर्त बताकर एवं बेवकूफी भरे बाध्यकारी कदमों से मायूसी एवं गुस्सा बढ़ाने का काम न करे। आखिरकार हम सबको पता है कि नेताओं, बाबुओं एवं आम आदमी में से असली चालबाज कौन है? इस पहले सिद्धांत को अमल में लाए बगैर हमें चक्रीय रूप से उतार-चढ़ाव का सामना करना होगा लेकिन कोई मूलभूत एवं त्वरित बदलाव नहीं होगा। इसके लिए पूंजी एवं श्रम की उच्च उत्पादकता की जरूरत होती है।

मुझे इस बात पर काफी चर्चा देखने को मिलती है कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सात अंधों की कहानी की तरह हरेक विशेषज्ञ समस्या के अलग-अलग हिस्सों को देखता है और फिर यह सोचकर समाधान भी सुझाता है कि वह पूरी समस्या दूर कर देगा। किसी को लगता है कि ब्याज दरों में अधिक कटौती करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी जबकि दूसरा विशेषज्ञ व्यक्तिगत आयकर को खत्म करने का सुझाव देता है। नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने मौजूदा सुस्ती के लिए आर्थिक सुधारों को जिम्मेदार बताया है। लेकिन समस्या इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को प्रधान सेवक कहते हों लेकिन अमूमन सारे नेता पिछली सरकार के नेताओं की ही तरह दंभी एवं जिद्दी नजर आते हैं। हाल ही में एक मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे एक कारोबारी ने उस मंत्री को 'लड़ाई पर उतारू, सुस्ती को लेकर असंवेदनशील और सुनने के लिए तैयार नहीं' करार दिया।

इसकी उम्मीद कम ही है कि जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों की गूंज शासकों के कानों तक पहुंच पाएगी। साफ तौर पर व्यावहारिक लोगों को सरकार से थोड़ी-बहुत मरम्मत से अधिक की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। यह चर्चा ही निरर्थक है कि सरकार क्या कुछ कर सकती है? रोडमैप का पता नहीं है, वृद्धि का पहला सिद्धांत नदारद है और नीति-निर्माताओं के आंख-कान बंद पड़े हैं। अर्थव्यवस्था की गिरावट का मौजूदा दौर अगले कुछ वर्षों में खुद ही खत्म हो जाएगा लेकिन संरचनात्मक मुद्दे फिर भी कायम रहेंगे। इन संरचनात्मक मुद्दों ने ही पिरामिड के निचले हिस्से में मौजूद लोगों के जीवन की गुणवत्ता में जल्द सुधार और तीव्र आर्थिक वृद्धि को रोका हुआ है।

जलवायु परिवर्तन से जुड़ी प्रवासन की बढ़ती समस्या

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

मैं एक ऐसी तस्वीर साझा कर रही हूं जो मेरे जेहन से निकल ही नहीं रही है। हम एक कमरे में कैद हैं और वहां मौजूद छोटी सी खिड़की से देख पा रहे हैं कि बाहर का मौसम बेहद खराब हो चुका है। जंगलों में आग लगी हुई है, गर्म हवाएं चल रही हैं, तेज बारिश हो रही है और तूफान आया हुआ है। यह सबकुछ पहले जताई आशंकाओं के अनुरूप है लेकिन हमारी चीखें नहीं सुनी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो यह सब कहीं और चल रहा है, मानो यह हकीकत न हो।

मुझे पता है कि यह बहुत नाटकीय प्रतीत होता है लेकिन यह तथ्य है। तेजी से बदलते मौसमी रुझानों और पृथ्वी पर बढ़ती गर्मी का असर हमारे सामने है। लेकिन हमारा ध्यान व्यापार युद्ध, ब्रेक्सिट, आव्रजन, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रवाद, युद्ध जैसी बातों में लगा हुआ है। मानव इतिहास में जलवायु परिवर्तन शायद इससे बुरे वक्त में नहीं हो सकता था। हम इससे निपटने में असमर्थ नजर आ रहे हैं।

यही वह वक्त है जब यह स्पष्ट हो चला है कि चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। हर वर्ष हमें कहा जाता है कि यह सबसे गर्म वर्ष है। अगले वर्ष यही कहानी दोहराई जाती है। इसके बाद एक नया रिकॉर्ड टूटता है। हालात निरंतर बिगड़ते जा रहे हैं। हम सबको यह पता है, हम इसे महसूस कर सकते हैं।

हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अपने अस्तित्व की चुनौती से जूझ रहे लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? बात चाहे सूखे की हो या बाढ़ की, लोगों को इनकी वजह से मजबूरन काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। ये लोगों को घर से बाहर निकलने पर मजबूर करते हैं। कई बार यह अस्थायी होता है और कई बार उनका यह प्रवास स्थायी हो जाता है। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन का खतरा मुंह बाये हमारे सामने खड़ा है।

अमिताभ घोष अपने नए उपन्यास गन आइलैंड में हमें प्रवासियों की पीढ़ियों से मिलाते हैं। जहां अतीत और वर्तमान में लोगों को नई आजीविका की तलाश में अपना घर बार छोड़कर निकलना पड़ा। प्रवासी हमेशा से बदलाव का मानवीय चेहरा रहे हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह भी सच है कि प्रवास केवल मजबूरन नहीं किया जाता बल्कि कई बार लोग दूसरी जगह बेहतर भविष्य की उम्मीद में भी अपना घरबार छोड़ते हैं।

पूरी दुनिया आपस में इस कदर जुड़ी हुई है कि इसके कई तरह के असर हमारे सामने हैं। एक तो यह कि एक देश का कार्बन डाई ऑक्साइड पूरी दुनिया के वातावरण को प्रभावित करता है। दूसरा दुनिया भर के समाचार मोबाइल टेलीफोनी की गति से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इस संदर्भ में देखें तो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना भी बढ़ेगा।

सवाल यह है कि इस तेज गति से हो रहे प्रवासन को लेकर हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। प्रवासन पहले ही कई देशों की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। भारत में हम इस बात पर चर्चा करते हैं 'बाहरी लोगों' की गणना कैसे की जाए। हमें यह भी पता नहीं कि एक बार उनकी गिनती हो जाने के बाद क्या होगा? यूरोप में जनता का मिजाज उन तस्वीरों से निर्धारित हो रहा है जिनमें नौकाओं पर सवार लोग बड़ी तादाद में अवैध तरीके से देश पहुंच रहे हैं। अमेरिका में दीवार खड़ी की जा रही है और लाखों लोग अमेरिका प्रवेश की आकांक्षा लिए खड़े हैं। सोशल मीडिया से लेकर तमाम सार्वजनिक जगहों पर यह सब चर्चा का विषय है। प्रवासियों को लेकर चल रही बहस वास्तविक है और इससे निपटने की हमारी प्रतिक्रिया काफी हद तक नाकाफी है। हमारे कदम और शब्द इसके लिए नाकाफी हैं। यही वजह है कि समाज में पहले ही इसे लेकर असुरक्षा और भय का माहौल बन गया है। इससे समुदायों के बीच कड़वाहट बढ़ रही है और ध्रुवीकरण हो रहा है। इसका फायदा राष्ट्रवादी दल उठा रहे हैं।

याद कीजिए कि अमेरिका के टैक्सस शहर के अल पासो में जब एक श्वेत व्यक्ति ने लोगों पर गोलीबारी की तो उसने कहा कि वह यह काम दुनिया को जलवायु संकट से बचाने के लिए कर रहा है। उसने अपने ब्लॉग पर दलील दी थी कि अमेरिकी कभी अपनी जीवनशैली नहीं त्यागेंगे, हालांकि वह मानता है कि यह पूरी पृथ्वी को नष्ट कर रही है। उसका जवाब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाप्त करने से अमेरिकी जीवन शैली को निभाना संभव होगा। वह लोगों को मारकर अमेरिका में प्रवेश करने से रोकना चाहता था।

अतीत में मैंने ऐसी हरकतों को पागलपन कहकर खारिज किया था। परंतु अब हम ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जहां संकट के दो कोण मिलेंगे और स्थितियां विस्फोटक होंगी। अभी भी हमारे पास प्रवासन को लेकर समुचित आंकड़े नहीं हैं। हम जलवायु कारणों से बने शरणार्थियों के बारे में सहजता से इसलिए बात करते हैं क्योंकि इस समस्या की प्रकृति और गंभीरता को समझना आसान नहीं।

कहने का अर्थ यह नहीं है कि प्रवासन बुरा है। सच तो यह है कि तमाम शहर और देश बने ही इसलिए क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसे। हमारे देश में आंतरिक प्रवासन की समस्या रोजगार से जुड़ी है। हर क्षेत्र में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बाढ़ या सूखाग्रस्त क्षेत्रों से वहां आए हैं। कई लोग रोजगार की तलाश में आते हैं।

हमारे देश में ऐसे लोगों से जुड़ा कोई आंकड़ा नहीं है क्योंकि पिछली जनगणना दशक भर पहले हुई थी। परंतु शहरों के आसपास अवैध बस्तियों को देखकर यह तय है कि बड़ी तादाद में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इसका राजनीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव नजर आता है। हालात आगे और खराब होंगे।

मैं इस लेख का समापन नहीं कर रही हूं क्योंकि मेरे पास कोई निष्कर्ष नहीं है। परंतु मैं मानती हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम जलवायु परिवर्तन की प्रकृति पर मानवीय ढंग से चर्चा करें।

कानाफूसी

नायडू की उपलब्धियां

देश के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने गत रविवार को बतौर उपराष्ट्रपति दो वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस मौके पर चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने नायडू की पुस्तक लिसनिंग, लर्निंग, लीडिंग का लोकार्पण करते हुए उनके दो वर्ष के कार्यकाल को ऊर्जा से भरा हुआ और भारी व्यस्तता वाला बताया। पुस्तक में नायडू कहते हैं कि वह हमेशा देश को बदलने में अपनी भूमिका के बारे में सोचते रहे। उनके कार्यालय के अनुसार नायडू ने इस अवधि में 330 बार बड़े सार्वजनिक आयोजनों में शिरकत की। राज्य सभा की बैठकों का 123 बार संचालन किया और 19 देशों की यात्रा की। कुल 257 पृष्ठों की इस पुस्तक में नायडू की 232 तस्वीरें हैं और एक अध्याय राज्य सभा के कामकाज में आए बदलाव पर है। पुस्तक में नायडू द्वारा राज्य सभा में की गई ई-नोटिस की पहल की सफलता का विस्तार से ब्योरा दिया गया है। हाल में समाप्त हुए राज्य सभा के सत्र में सांसदों ने ऑनलाइन तरीके से 9,000 नोटिस दिए। कुल नोटिस में इनकी हिस्सेदारी 60 फीसदी थी।

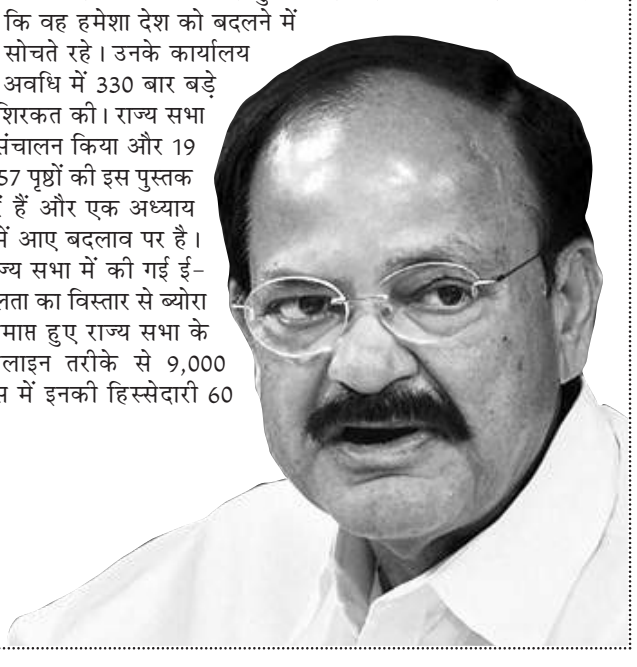

आपका पक्ष

पश्चिमी तटीय राज्यों में बाढ़ से तबाही

केरल, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में भारी बारिश से आई बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। केरल में बाढ़ और भूस्खलन से 59 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां 14 जिलों में बाढ़ से बचाव के लिए 1,318 राहत शिविर बनाए गए हैं। कर्नाटक में 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। वहां बाढ़ के कारण 40 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 1,168 राहत शिविर बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। वहां 369 राहत शिविर बनाए गए हैं। देश के पश्चिमी तटीय राज्यों में बारिश का कहर जारी है। ऐसे में लोगों को उनकी मदद के आगे आना चाहिए। रेलवे ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में माल ढुलाई नि:शुल्क करने का फैसला लिया है। देश के अन्य राज्यों से इन राज्यों में मदद की दरकार है। अगर लोग प्रकृति की मार झेल रहे इन लोगों की मदद करने के लिए अपने हाथ बढ़ाएंगे तो देश में एकता की भावना मजबूत होगी।

एनडीआरएफ के जवानों ने कर्नाटक के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से लोगों को निकाला -पीटीआई

कई स्वयंसेवी संगठन अपने-अपने क्षेत्रों में सामान जमा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजते हैं। इससे बाढ़ प्रभावित लोगों को काफी मदद मिल जाती है। देश के कई राज्य समय-समय पर प्राकृतिक आपदा के शिकार होते रहते हैं। सरकार राहत अभियान चलाती है लेकिन पुनर्वास पर अधिक ध्यान नहीं देती है। ऐसे लोग जिनका घर प्राकृतिक आपदा में तबाह हो जाता है उन्हें सरकार की ओर से घर बनाने में मदद मिलनी चाहिए।

अनुराधा कुमारी, नई दिल्ली

बाजार के चंगुल से बचाने की कोशिश

देश भर में राज्य और केंद्र सरकार तक के स्वास्थ्य विभाग की मौजूदा स्थिति गंभीर है। इससे आने वाले दिनों में भी स्वास्थ्य सुविधा के विपरीत व्यक्ति अधिक से अधिक बीमारियों से ग्रसित होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रति 1,000 व्यक्ति पर एक चिकित्सक होने की बात करता है, जबकि हमारे यहां 11,000 लोगों पर एक चिकित्सक है। चिकित्सा सेवाओं के लिए जब उपभोक्ता भारी भरकम भुगतान करते हैं, ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि चिकित्सा सेवाओं को भी उपभोक्ता के नजरिये से जांचा परखा जाए। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को परोपकार के नजरिये से देखा जाता था। आज स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बाजार आधारित हो गई। ऐसे में इन सेवाओं को कानून के दायरे में लाना जरूरी है।

दीप कुमार, महाराजगंज

बीमार स्वास्थ्य सेवाओं को दवा

आंकड़ों की मानें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में विगत वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। इसमें बिहार गरीब बच्चों की मौतों को लेकर सुर्खियों में रहा है। वर्ष 2017 में बनी एक स्वास्थ्य नीति की संसद में घोषणा करते हुए कहा गया था कि जीडीपी का दोगुना इस मद में व्यय किया जाएगा। जबकि बजट घोषणा करते हुए व्यय को कम कर दिया गया। इसे क्या कहा जाए? वास्तविक स्थिति यह है कि नए कानून बनाने, योजनाएं व उनके मद में बजट आवंटित करने की प्रक्रिया नाकाफी है। योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले तंत्र के स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करने से स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव दिखाई देगा।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।